SHRI G. VISWANATHAN: It should be discussed in the Rules Committee.

MR. SPEAKER: We have already devised a procedure. If the list is completed, then there will be a second round.

रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टालों में एकाधिकार की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये प्रस्ताव

*737. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय देश में रेलवे विभाग के विभिन्न जंक्शनों में बुक स्टालों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने अशिक्षित बेरोजगारों अथवा सहकारी संगठनों के पास हैं ,

(ख) क्या सरकार का विचार बुक स्टालों में एकाधिकार की प्रवृत्ति समाप्त करने का है , और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD SHAFI QURESHI). (a) There are 744 bookstalls on the entire Indian Railways Of this 19 bookstalls are at present held by unemployed graduates and by cooperatives/partnerships of unemployed graduates

(b) No monopoly right is enjoyed by any firm or any individual at present

(c) Does not arise

श्री शंकर दयाल सिंह : रेलवे बजट पर जब जब यहां चर्चायें होती हैं और इस साल भी हुई हैं तब तब सभी सदस्यों की ओर से, सभी दलों की ओर से यह मांग की गई है कि व्हीलर वगैरह का जो एकाधिकार बुकस्टालों पर है उसको समाप्त किया जाए । पिछले रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने भी सदन को आश्वासन दिया था और इस बार रेल मंत्री ने भी जो भाषण दिया उस में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला था । जिस तरह से आप सिलिंग आदि लागू कर रहे हैं जमीन पर, उद्योगों पर, उसी तरह से बुक स्टालों के सम्बन्ध में भी आप कोई नीति बनाएंगे कि एक व्यक्ति के अधिकार में एक या दो या चार से अधिक बुकस्टाल न रहें ? इस बात को मद्देनजर रखते हुए व्हीलर या दूसरी ऐसी जो भी संस्थायें हैं और जिन के पास बहुत अधिक बुक स्टाल हैं उन का एकाधिकार आप कब तक समाप्त करने जा रहे हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको परमानेंट अधिकार दिया गया है बुक स्टाल चलाने का । जब भी यह बात हमारे नोटिस में आएगी कि उनका काम तसल्लीबख्श तरीके से नहीं हो रहा है उस वक्त उनका कांट्रेक्ट खत्म किया जा सकता है । कुछ बुक स्टाल उन्होंने सरेंडर किए भी हैं और उनको हमने अनएम्प्लाइड ग्रेजुएट्स को देने की कोशिश की है ।

श्री शंकर दयाल सिंह : अध्यक्ष जी, जैसे सरकार ने कैटरिंग आदि की व्यवस्था बहुत जगह अपने हाथ ले ली है मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं सरकार उन बुक स्टालों को अपने हाथ में लेकर चलाने पर विचार करती है ?

मैं जान-बूझकर यह सवाल इसलिये पूछ रहा हूं कि बुक स्टालों पर जिस तरह का साहित्य रहता है, उसको देखने से पता चलता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या है ? कभी-कभी तो जासूसी पंजा, खूनी पंजा, मनोहर कहानियां इत्यादि ही वहां पर रहती हैं । अच्छा साहित्य नहीं रखा जाता है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन बुक स्टालों पर अच्छा साहित्य रहे, इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ? और क्या सरकार का ऐसा विचार है कि

जिस तरह से कैंटीरग वगैरा सरकार स्वयं चला रही है, वैसे ही बुक-स्टालों को भी स्वयं चलाये ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : बुक स्टालों को सरकार अपने तौर पर चलाये, इस तरह का विचार नही है । न ही इससे कोई लाभ होगा ।

जहा तक किताबों का तालुक है, हमारी तरफ से स्टेशनों पर और प्लेटफार्मो पर जो कमेटी बनी हुई है, वह इस बात की पूरी जांच करती है कि पढ़ने के लिये वही किताबे मार्केट में आये जिनमे तहजीब के और इखलाक के खिलाफ बाते दर्ज न हो । लेकिन बदकिस्मती से जो खूनी पंजा या इस किस्म की किताबें आ जाती है उनकी जांच की जा रही है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है इस बात पर कि पढने वाले का शौक क्या है ?

श्री शंकर दयाल सिंह : आपकी इजाजत से, अध्यक्ष जी, मैं एक सवाल यह पूछना चाहता हू । आप जानते है, खुद भी देखते है कि उन बुक स्टालों पर इस तरह की किताबें रहती है । क्या इस तरह के अपराध पर अभी तक किसी बुक-स्टाल का करार रद्द कर किया गया है ?

श्री राम सहाय पांडे : खूनी पंजा तो अच्छी किताब है ।

अध्यक्ष महोदय : इखलाक भी आदमी आदमी पर मुन्हस्सर होता है ।

SHRI G. VISWANATHAN: The hon. Minister stated that there was no monopoly concern in the railway bookstalls. I think he is not correct. I would like to know from the hon. Minister how many bookstalls have been given to Wheeler and how many to Higginbothams in the whole of South India.

MR. SPEAKER: You are asking a question on some statistical information.

SHRI G. VISWANATHAN: It comes under the question.

MR. SPEAKER: South India.

SHRI G. VISWANATHAN: Let him give for the whole of India. I never put an irrelevant question.

SHRI MDHD. SHAFI QURESHI: Wheelers are having 381 bookstalls and Higginbothams have got 49 bookstalls.

SHRI G. VISWANATHAN: He says there is no monopoly. What else is this?

SHRI MOHD SHAFI QURESHI: They are our licensees. There is a contract between them and us. We can terminate the contract any time we like. How is it a monopoly?

SHRI BISWANARAYAN SHASTRI: Pursuing the question of Shri Shankar Dayal Singh, I would like to know from the hon. Minister whether he proposes to have an Advisory Committee for the railways for selecting books, so that passengers can have good literature at the bookstalls.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : There was a Bookstall Committee for each division. They were amalgamated later on with the Zonal Consultative Committee. But now we are trying to revive these committees, and there will be a Bookstall Committee for each zone.

श्री दस्सोदर पांडे : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो गन्दी गन्दी किताबें वहां बुक-स्टालों पर रहती है, शायद उसकी जानकारी उनको पूरी नही है, लेकिन क्या यह जानकारी है कि जो सरकारी प्रकाशन है, अच्छी किताबे है वह वहां पर बिल्कुल नही रहती है ? क्या इस प्रकार की व्यवस्था वह करेंगे कि सरकार के जो अच्छे प्रकाशन है, जो सरकार द्वारा उपयोगी पुस्तक छापी जाती है, उन किताबों को उन बुक-स्टालों पर रखा जाये और उनको वहां बेचने की कोशिश की जाये ?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : ऐसी किताबें भी हैं। लेकिन यह पढ़ने वाले के शौक पर डिपंड करता है कि वह कौनसी किताब पढता हे।

श्री दामोदर पाँडे : ऐसी किताबे उन बुक-स्टालों पर नही होतीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : सफर मे धार्मिक किताबे पढ़ाई जाये, और आपकी छापी हुई किताबे पढाई जाये।

श्री जनेश्वर मिश्र : अभी मत्री महोदय ने व्हीलर कपनी की चर्चा करते हुये बताया कि उसके माथ हमारा कट्रेक्ट है। उस कट्रेक्ट को बढाते है तो वह कट्रेक्ट खत्म भी कर सकते है। हम जानना चाहते हैं कि क्या रेलवे स्टेशनों पर किताबो को बेचने के लिये कट्रेक्ट टेंडर पब्लिकली इन्वाइट किये जाते है? उसमे कपीटीशन के क्या तरीके होते है?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री शकर दयाल सिंह जी को बधाई देना चाहता हू कि आज वह यहा हैं। इसके पहले 8 महीने से मैं लगातार देखता आ रहा हू कि जब कभी रेलवे के बुक-स्टाल पर प्रश्न आता है तो जिस के नाम मे वह होता है वह मेम्बर उस समय गायब रहता है। हम सोचा करते थे कि क्या दबाव पडता है? यह दबाव न केवल हम लोगों पर बल्कि मंत्रालय पर भी पडता है। (व्यवधान) मैं जानता हू वह इलाहाबाद का है और किस तरह से लोगों पर दबाव डालता है। वह हमारा विरोधी हे। ऐसा मत समझिये कि मैं उसे जानता नही हू।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या पब्लिकली कभी कंट्रेक्ट टैंडर रेलवे बुक-स्टालों के लिये मगाये जाते हैं? इन्होंने एक ही फर्म को बताया है जो 300 से ऊपर जगह पर किताबे बेचती है। मैं जानना चाहता हूं कि 300 पर, 500 पर या हजार पर कितने पर आप मोनोपली मानेंगे? कितने स्टालों पर उसकी मोनोपली मानी जायेगी यह बताया जाये?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इसका बाकायदा अखबारो मे चर्चा किया जाता है। जब भी कोई बुक-स्टाल खाली होता है, उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। उसके बाद जो आते है, एक लाइसेंस सिस्टम है ढाई परसेंट रोयल्टि या लाइसेंस फीस लेकर उसे हैं देते है। अभी 256 बुक स्टाल खाली पडे हैं जिसका हमने बाकायदा एडवरटाजमेंट हर अखबार मे किया कि जो अन-एम्प्लाइज ग्रैज्युएट्स है वह एप्लाई करें। 19 दरख्वास्ते अन-एम्प्लायड ग्रेज्युएट्स की आई है। बाकी 200 से ज्यादा स्टाल खाली पडे हैं। अगर कोई दरख्वास्ते आयेंगी तो हम तमलीम कर लेंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि उन बुक स्टालों पर कैसा और कौनसा साहित्य बिके, क्या इसकी कोई सूची आपने बुक-स्टालो को दी है। यदि हां, तो कौनसी सूची है? क्या यह बात सही है कि रेलवे बोर्ड ने जोनल को और जोनल ने डी० एस० को आदेश दिये हैं कि कुछ समाचार-पत्र साप्ताहिक और दैनिक इन स्टालो पर न बिकें जैसे आर्गेनाइजर, पाचजन्य और मदरलैंड है? क्या यह सही हे?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कोई अखबार, किताब या रिसाला किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, इस बुनियाद पर उसको स्टाल पर बेचने से मना नही किया जाता है। अगर गवर्नमेंट किसी को बैन करती है तो उसका असर जरूर हमारे ऊपर पड़ता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैंने सूची की बात पूछी है क्या कोई सूची है?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : नहीं, ऐसा नही है।

श्री हरि किशोर सिंह : क्या रेलवे में ऐसी व्यवस्था है कि बुक स्टाल का सब-कंट्रेक्ट दिया जाये ? क्योंकि यह कंट्रेक्ट व्हीलर कंपनी वाले लेते हैं । मेरी जानकारी जितनी है उसके अनुसार वे सब कंट्रेक्ट देते हैं । क्या ऐसी व्यवस्था है या नहीं ? अगर यह व्यवस्था गैर-कानूनी है तो इस पर मंत्री महोदय क्या कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जो लाइसेंस दिया जाता है वह तो ट्रांसफर नहीं कर सकते । लेकिन लाइसेंस को यह हक है कि वह अपना एजेन्ट मुकर्रर कर के अपना कारोबार चलाये ।

Jaipur Udyog Limited

*738. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to the fact that serious crisis is being faced by the Jaipur Udyog Limited, the biggest cement concern in Asia belonging to Aloka Udyog Group due to utter mismanagemnt of its affairs and misuse of funds;

(b) whether a newsitem appearing in 'New Age Weekly' dated the 30th March 1974 concerning this has been brought to the notice of Government;

(c) if so, reaction of Government thereto ; and

(d) the steps so far taken for putting an end to these practices?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (SHRI BEDABRATA BARUA): (a) Government are aware that Jaipur Udyog Ltd. has incurred heavy losses during its accounting years 1971-72, 1972-73 and 1973-74.

(b) and (c) Government have seen a news report in the 'New Age' of 30th March, 1975 (and is not aware of any such report on 30th March, 1974) which alleges, inter alia, that Jaipur Udyog Ltd. has defaulted in the repayment of loans and in the deposit of employees' provident fund and compulsory deposit amounts.

(d) An inspection of the books of accounts of Jaipur Udyog Ltd. has been carried out in 1973, and action in respect of the irregularities and contraventions of the Companies Act, 1956 are being taken by the Registrar of Companies. In respect of other matters for which action by other Departments or Ministries are required, necessary particulars have been furnished to them.

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: I may say that the Government is making an attempt to play down the seriousness of the matter involved in the question. This company is the biggest cement factory in our country, which is heavily financed by loans by the Rajasthan Government and it has also been given calcium mines at subsidised rates by the Rajasthan Government. Sir, this company is producing only 30% of its installed capacity.

(Interruption)

When the whole country is facing such a serious cement crisis, they are producing only 30% of the installed capacity.

Moreover, the spending by the Directors of the company has landed the company today in near bankruptcy. They have to pay crores or lakhs of rupees to the Punjab National Bank, and the bank is now taking measures to. . .

MR. SPEAKER: What is your question?

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: My question was clear but the Government did not answer it properly; and that is why I am asking again. What I am saying is that there are serious allegations against this company and I am asking whether the Government is going to take some measures with a sense of emergency so that the monopoly house can be brought to book.

SHRI BEDABRATA BARUA: I have already stated that we have taken a